अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

रजि.न.34300/80 | संख्या 114 | श्री विजय पुरम, गुरूवार, 30 अप्रैल 2026 | web: dt.andamannicobar.gov.in | 2.00 रूपए

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रयास हेतु प्रशासन की तैयारी

जलमार्ग खाली रखने हेतु नाविकों व जल क्रीड़ा संचालकों हेतु दिशा–निर्देश जारी

श्री विजय पुरम, 29 अप्रैल

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड (जीडब्ल्यूआर) बनाने के प्रयास किए जाएंगे, जिनमें 'पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराना' (60 मीटर 40 मीटर; 2,400 वर्ग मीटर) तथा 'पानी के भीतर सबसे ऊंचा मानव स्तंभ' (20 मीटर ऊंचाई) शामिल हैं। 'सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराना' कार्यक्रम 2 मई को राधानगर सागर तट पर आयोजित किया जाएगा, जबकि 'सबसे ऊंचा मानव स्तंभ' 3 मई को स्वराज द्वीप जेटी स्थित लाइटहाउस के निकट प्रस्तावित है।

सूचना, प्रचार एवं पर्यटन विभाग से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस संबंध में अनुरोध किया गया है कि स्वराज द्वीप जेटी की ओर आने वाली नौकाओं के लिए नेविगेशन चैनल 30 अप्रैल एवं 3 मई, 2026 को प्रातः 8 बजे से 11.30 बजे तक सभी प्रकार की नौकाओं के आवागमन से मुक्त रखा जाए, ताकि 'पानी के भीतर सबसे ऊंचा मानव स्तंभ' रिकॉर्ड प्रयास सुचारु रूप से संपन्न हो सके।

इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान लाइटहाउस के पास नेविगेशन चैनल के आसपास एफआरपी नौकाएं एवं सभी जल क्रीड़ा गतिविधियां भी पूर्णतः बंद रखी जाएं, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और रिकॉर्ड प्रयासों का संचालन सुचारु रूप से किया जा सके।

उद्योग निदेशालय द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

श्री विजय पुरम, 29 अप्रैल।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के उद्योग निदेशालय ने भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सहयोग से 29 अप्रैल, 2026 को श्री विजय पुरम स्थित उद्योग निदेशालय के सम्मेलन सभागार में एक दिवसीय इन–सर्विस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम उद्योग निदेशक श्री अतुल सोनी और सचिव (उद्योग) श्रीमती पल्लवी सरकार (भा.प्र.से) के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की क्षमता बढ़ाना था, ताकि वे एमएसएमई से जुड़ी योजनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकें और लागू कर सकें। विशेष रूप से विश्व बैंक द्वारा समर्थित 'राइजिंग एंड एक्सेलेरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस' कार्यक्रम, विभिन्न योजनाओं, डिजिटल प्लेटफॉर्म और एमएसएमई विकास से जुड़े उपायों पर ध्यान दिया गया।

तकनीकी सत्र की शुरुआत एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार के उप निदेशक श्री नरेंद्र जेना के संबोधन से हुई। उन्होंने मंत्रालय की भूमिका और एमएसएमई को बढ़ावा देने वाली प्रमुख योजनाओं के बारे में जानकारी दी।

इसके बाद नेशनल पीएमयू (आरएएमपी) के सदस्य डॉ. मिलन शर्मा और श्री विजय शर्मा (कार्यक्रम प्रबंधक, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) ने आरएएमपी की विभिन्न उप–योजनाओं और एमएसएमई पहल पर प्रस्तुतियां दीं। इनमें ग्रीनिंग पहल, टीम पहल, ऑनलाइन विवाद समाधान, उद्यमी भारत पोर्टल, एमएसएमई चैंपियंस योजना, नेशनल एससी/एसटी हब, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट और एमएसई–क्लस्टर विकास कार्यक्रम शामिल थे।

कार्यक्रम के अंत में उप निदेशक (मुख्यालय) श्री अजीत आनंद ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। उन्होंने एमएसएमई मंत्रालय का इस उपयोगी प्रशिक्षण के लिए आभार व्यक्त किया और अधिकारियों से अपील की कि वे इस प्रशिक्षण से मिली जानकारी का उपयोग द्वीप समूह में एमएसएमई के विकास और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में उपयोग करें।

दक्षिण अण्डमान में राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण पर जिला स्तरीय बैठक आयोजित

श्री विजय पुरम, 29 अप्रैल

"ज्ञान भारतम् मिशन" के अंतर्गत राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण पर आज प्रातः 11.30 बजे दक्षिण अण्डमान के उपायुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में एक जिला स्तरीय बैठक अपर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक के दौरान अपर जिला मजिस्ट्रेट ने भारत सरकार की इस सराहनीय पहल पर प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य देश की समृद्ध सांस्कृतिक एवं बौद्धिक धरोहर का संरक्षण करना है। ज्ञान भारतम् मिशन के तहत पूरे देश में हस्तलिखित ग्रंथों, पांडुलिपियों तथा सदियों पुराने अभिलेखों की पहचान एवं प्रलेखन के लिए समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। इस पहल के अंतर्गत आधुनिक तकनीक का उपयोग कर इन अमूल्य धरोहरों का डिजिटलीकरण भी किया जा रहा है, जिससे उनका दीर्घकालिक संरक्षण सुनिश्चित हो सके तथा भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनकी सुलभता बनी रहे। यह भी रेखांकित किया गया कि यह सर्वेक्षण ऐतिहासिक दस्तावेजों और पांडुलिपियों में निहित विशाल ज्ञान के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार अपर जिला मजिस्ट्रेट ने सभी संबंधित पक्षों से इस पहल में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया तथा पुराने दस्तावेजों को एकत्रित कर उन्हें निर्धारित मंचों पर अधिकतम संख्या में अपलोड करने का आग्रह किया। उन्होंने स्थानीय समुदायों और विद्यार्थियों के बीच पांडुलिपियों के महत्व तथा उनके संरक्षण की आवश्यकता के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर भी बल दिया।

बैठक का समापन इस आह्वान के साथ हुआ कि जिले में सर्वेक्षण के सफल क्रियान्वयन हेतु सभी विभागों और संस्थानों द्वारा समन्वित प्रयास किए जाएं।

दक्षिण अण्डमान जिला परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पद के लिए 7 मई को चुनाव

श्री विजय पुरम, 29 अप्रैल

यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दक्षिण अण्डमान जिला परिषद के पंचवर्षीय कार्यकाल (2022–2027) के लिए अध्यक्ष (अ) एवं उपाध्यक्ष (अ) पद हेतु चुनाव, जो 27 अप्रैल, 2026 को प्रातः 11 बजे आयोजित होना निर्धारित था, प्रशासनिक कारणों से स्थगित कर दिया गया है। अब यह चुनाव 7 मई, 2026 को प्रातः 10 बजे जिला परिषद, दक्षिण अण्डमान के सम्मेलन कक्ष में आयोजित किया जाएगा।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में ज्ञान भारतम् मिशन

पांडुलिपियों एवं अभिलेखीय धरोहर की पहचान, प्रलेखन और डिजिटलीकरण हेतु केंद्रशासित प्रदेश–स्तरीय पहल

द्वीपों की विरासत के संरक्षण के लिए लोगों से पांडुलिपियाँ साझा करने का आह्वान

श्री विजय पुरम, 29 अप्रैल

भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख पहल के रूप में ज्ञान भारतम् मिशन का शुभारंभ किया है। इस मिशन का उद्देश्य देशभर में शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों तथा निजी संग्रहों में उपलब्ध पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, प्रलेखन, संरक्षण, डिजिटलीकरण तथा उन्हें सुलभ बनाना है।

युवाओं को उनकी जड़ों से जोड़ने तथा प्राचीन ज्ञान को वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों तक सुलभ बनाने के उद्देश्य से अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के कला एवं संस्कृति विभाग ने भी तीनों जिलों में पुरानी पांडुलिपियों की पहचान, प्रलेखन और संरक्षण हेतु केंद्रशासित प्रदेश–स्तरीय मिशन प्रारंभ किया है।

इस पहल के अंतर्गत, स्थानीय निवासियों को ऐतिहासिक दस्तावेज, मानचित्र एवं पुरानी तस्वीरें कला एवं संस्कृति विभाग को उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि उन्हें ज्ञान भारतम् सर्वे ऐप पर अपलोड किया जा सके। अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन का कला एवं संस्कृति विभाग द्वीपों की अभिलेखीय धरोहर के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में विभाग आम जनता, संस्थानों, शोधकर्ताओं एवं संग्रहकर्ताओं से निम्नलिखित माध्यमों से सहयोग करने का आग्रह करता है:

- ऐतिहासिक महत्व की पांडुलिपियों एवं अभिलेखीय सामग्री का दान या साझा करना।
- व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के पास उपलब्ध ऐसी सामग्रियों के संबंध में जानकारी प्रदान करना।
- द्वीपों से संबंधित दुर्लभ एवं मूल्यवान अभिलेखों की पहचान एवं प्रलेखन में सहयोग देना।

प्रशासन यह आश्वासन देता है कि ऐसी सामग्रियों के संरक्षण, प्रलेखन एवं डिजिटलीकरण के लिए आवश्यक विशेषज्ञता उपलब्ध कराई जाएगी। योगदानकर्ताओं को विधिवत मान्यता दी जाएगी तथा सामग्री का स्वामित्व मूल धारकों के पास ही रहेगा, केवल उनकी डिजिटल प्रतियाँ संरक्षण एवं शोध के उद्देश्य से अभिलेखागार में सुरक्षित रखी जाएंगी।

इच्छुक व्यक्ति पांडुलिपियों एवं अभिलेखीय सामग्रियों का

शेष पृष्ठ 4 पर

"लीकेज रोकें, पानी बचाएं" अभियान के तहत जल संरक्षण पर जोर

श्री विजय पुरम, 29 अप्रैल

श्री विजय पुरम नगरपालिका परिषद दिनांक 28 फरवरी, 2026 को प्रारंभ किए गए "लीकेज रोकें, पानी बचाएं" अभियान के क्रम में ने जल प्रबंधन एवं संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। ग्रीष्म ऋतु के आगमन तथा बांधों में जल स्तर में कमी के मद्देनज़र सभी वार्डों में सतत एवं समान जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु पानी के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। यह अभियान जल हानि को कम करने, जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने तथा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है और इसे प्राथमिकता के आधार पर निरंतर लागू किया जा रहा है।

इन प्रयासों के तहत एसवीपीएमसी ने अब तक वितरण प्रणाली में लीकेज की पहचान एवं समय पर मरम्मत के माध्यम से 33,500 लीटर पानी का सफलतापूर्वक संरक्षण किया है। नियमित निरीक्षण, पाइपलाइन, वाल्व एवं फिटिंग्स की त्वरित मरम्मत तथा ओवरफ्लो एवं लीकेज बिंदुओं की निगरानी से जल अपव्यय में उल्लेखनीय कमी आई है और बढ़ती मांग के इस समय में आपूर्ति दक्षता में सुधार हुआ है।

एसवीपीएमसी ने जोर दिया है कि जल संरक्षण केवल प्रशासन के प्रयासों से संभव नहीं है, इसके लिए आम जनता की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने घरों की पाइपलाइन एवं नलों की नियमित जांच करें, लीकेज को तुरंत ठीक कराएं, ओवरहेड टैंकों से पानी के बहाव को रोकें तथा जल के जिम्मेदार उपयोग को अपनाएं। ओवरहेड टैंकों में फ्लोट वाल्व लगाने की भी सिफारिश की गई है, ताकि अनावश्यक जल अपव्यय को रोका जा सके। नागरिक सार्वजनिक जल आपूर्ति में किसी भी प्रकार के लीकेज की सूचना एसवीपीएमसी के हेल्पलाइन नंबर 03192–231179 पर दे सकते हैं।

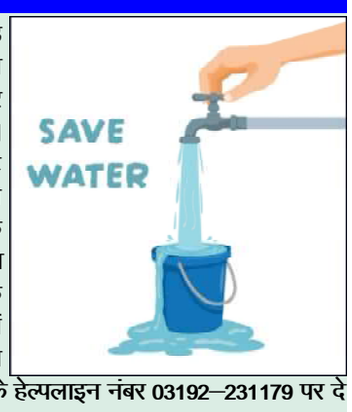

परिषद ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस प्रयास में सक्रिय भागीदार बनें और लीकेज, पाइपलाइन फटने या जल के दुरुपयोग की सूचना तुरंत दें। आज बचाई गई हर बूंद पूरे समुदाय के लिए भविष्य में जल उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होगी। एसवीपीएमसी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि परिषद इस महत्वपूर्ण संसाधन की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और सभी निवासियों से जल संरक्षण को सामूहिक नागरिक जिम्मेदारी के रूप में अपनाने का आग्रह करती है।

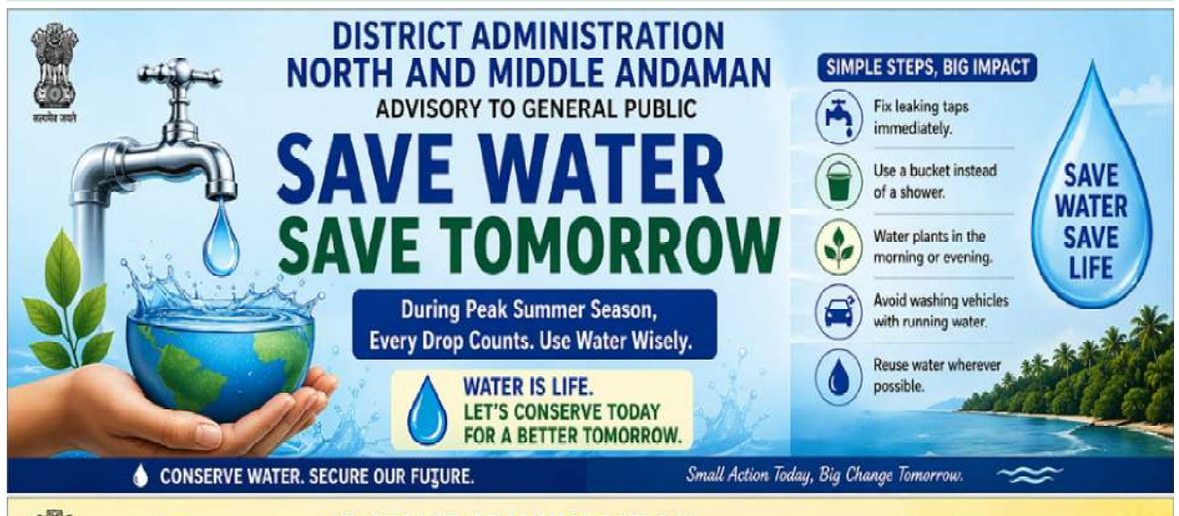

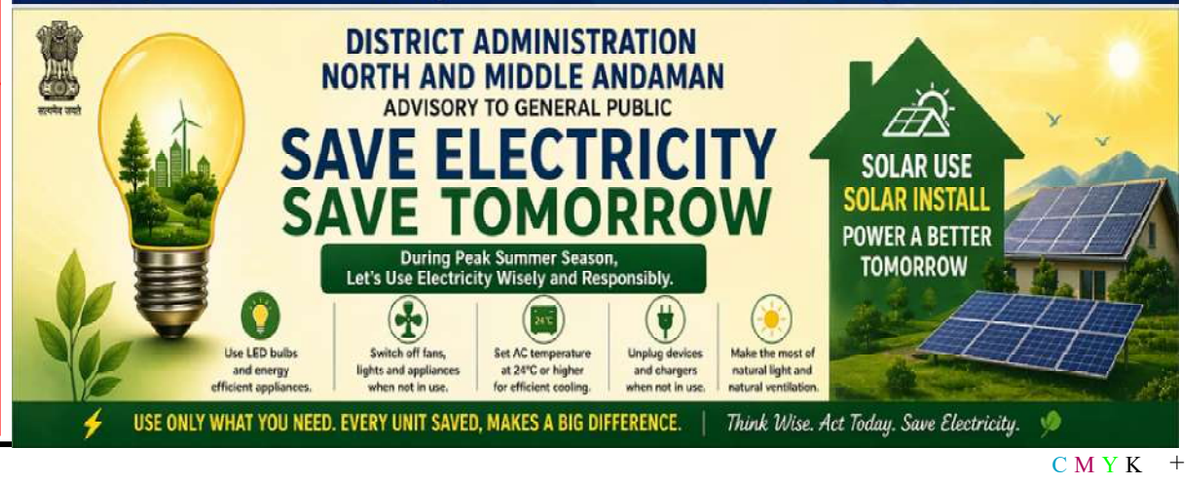

रंगत शैक्षिक जोन में ग्रीष्मकालीन कोचिंग कक्षाएं 5 मई से

रंगत, 29 अप्रैल

ग्रीष्मावकाश के दौरान रंगत शैक्षिक जोन का क्षेत्रीय कार्यालय 10 से 16 वर्ष आयु वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिए विभिन्न स्थानों बाराटांग, कदमतला, रंगत एवं बिल्लीग्राउंड में समर कोचिंग कक्षाओं का आयोजन करेगा। यह कोचिंग शिविर 5 मई, 2026 से प्रारंभ होगा, जिससे अधिक से अधिक बच्चे अपनी रुचि और पसंद के अनुसार इन कक्षाओं में भाग ले सकें। इससे बच्चों में खेलों के प्रति रुचि बढ़ेगी, भविष्य में खेलों में करियर बनाने में सहायता मिलेगी तथा वे विभिन्न स्तर की प्रतियोगिताओं में भी भाग ले सकेंगे। रंगत के जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों में प्रतिभा को निखारना और खेल कौशल का विकास करना है।

आईसीएआर–केवीके उत्तर व मध्य अण्डमान द्वारा गोविंदपुर में सतत कृषि हेतु संतुलित उर्वरक उपयोग पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

मायाबंदर, 29 अप्रैल

आईसीएआर–कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), उत्तर व मध्य अण्डमान द्वारा गोविंदपुर गांव में सतत फसल उत्पादन के लिए उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को उर्वरकों के विवेकपूर्ण एवं आवश्यकता–आधारित उपयोग के बारे में जागरूक करना था, जिसमें मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन तथा दीर्घकालिक उत्पादकता एवं पर्यावरणीय स्थिरता के लिए जैविक इनपुट के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया गया।

विषय विशेषज्ञ (कृषि विज्ञान) डॉ. राकेश डावर ने मृदा उर्वरता बनाए रखने एवं फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए संतुलित उर्वरक उपयोग और वैज्ञानिक पोषक तत्व प्रबंधन के महत्व पर बल दिया। विषय विशेषज्ञ (गृह विज्ञान) श्री यथार्थ शर्मा ने सतत कृषि एवं स्वस्थ पर्यावरण को बढ़ावा देने में पर्यावरण अनुकूल पद्धतियों तथा घरेलू स्तर पर जागरूकता की भूमिका पर प्रकाश डाला।

किसानों को रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को कम करने के लिए भी जागरूक किया गया, जिससे पर्यावरण प्रदूषण को घटाया जा सके और मृदा स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। इस कार्यक्रम में स्थानीय किसानों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार यह कार्यक्रम आईसीएआर–सीआईएआरआई, श्री विजय पुरम के कार्यवाहक निदेशक डॉ. जय सुंदर के समग्र मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर लगभग 15 किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सतत कृषि पद्धतियों को अपने खेतों में प्रभावी रूप से अपनाने के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया।

निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की 33वीं बैठक आयोजित

56 दावों के निपटान हेतु 10.59 लाख रुपये की स्वीकृती

श्री विजय पुरम, 29 अप्रैल

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (एएनआईबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) के अध्यक्ष एवं श्रम एवं रोजगार सचिव श्री एल. कुमार (आईएएस) ने आज आपूर्ति लाइन स्थित श्रम आयुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में बोर्ड की 33वीं बैठक आयोजित की। बैठक में केंद्र सरकार के नामित सदस्य, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के प्रतिनिधि, नियोक्ता एवं श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभों के विस्तार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। अध्यक्ष ने सभी पात्र लाभार्थियों तक कल्याणकारी लाभों के प्रभावी एवं समयबद्ध वितरण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने द्वीपों में विभिन्न निर्माण स्थलों पर कार्यरत श्रमिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता भी बताई, ताकि सभी पात्र श्रमिकों का बोर्ड में पंजीकरण सुनिश्चित हो सके और वे सामाजिक सुरक्षा सहायता का लाभ प्राप्त कर सकें।

कार्यसूची के बिंदुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श के बाद बोर्ड ने सर्वसम्मति से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत पात्र श्रमिकों द्वारा प्रस्तुत 56 दावों के निपटान हेतु 10.59 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की। इन दावों में पेंशन लाभ, मातृत्व लाभ, चिकित्सा सहायता एवं मृत्यु सहायता शामिल हैं। बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि स्वीकृत सभी वित्तीय सहायता राशि का वितरण प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता एवं दक्षता सुनिश्चित हो सके।

श्रम आयुक्त द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की स्थापना वर्ष 2009 में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। वर्तमान में बोर्ड पंजीकृत लाभार्थियों के लिए नौ कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रहा है। स्थापना के बाद से अब तक बोर्ड द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र श्रमिकों को कुल 36.66 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जा चुकी है।

अबर्डीन थाना पुलिस ने 24 घंटे के भीतर चोरी का मामला सुलझाया, सभी चोरी के सामान बरामद

श्री विजय पुरम, 29 अप्रैल

अटूट पेशेवर दक्षता और निरंतर प्रयासों का परिचय देते हुए अबर्डीन थाना पुलिस की टीम ने एक चोरी के मामले का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए चोरी गए सामान को बरामद किया तथा आरोपी को गिरफ्तार किया। दिनांक 25 अप्रैल, 2026 को अबर्डीन थाना में चोरी की शिकायत प्राप्त हुई, जिसके आधार पर तत्काल एक टीम का गठन किया गया, जिसमें उप–निरीक्षक दिनेश जायसवाल तथा पुलिस कांस्टेबल के. जगदीश बाबू, पी. मोहम्मद रफीक और संदीप केरकेट्टा शामिल थे। टीम ने कड़ी मेहनत, तकनीकी निगरानी और स्थानीय सूचना के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी का नाम सुनील कुमार, आयु 50 वर्ष, स्वर्गीय वासुदेवन का पुत्र, निवासी स्टीवर्टगंज, बम्बूफ्लाट है। आरोपी के कब्जे से चोरी गए सामान को बरामद कर सभी कानूनी औपचारिकताओं का पालन करते हुए जब्त किया गया।

इस मामले की जांच अबर्डीन थाना प्रभारी एसआईवी शिव कुमार के नेतृत्व में, दक्षिण अण्डमान के एसडीपीओ श्री दीपेंद्र कुमार सिंह (दानिप्स) के मार्गदर्शन तथा पुलिस अधीक्षक, दक्षिण अण्डमान जिला, श्रीमती श्वेता के. सुगाथन (आईपीएस) के समग्र पर्यवेक्षण में की गई। सामान्य जनता से अनुरोध किया जाता है कि किसी भी अपराध या अवैध गतिविधि से संबंधित सूचना पुलिस को 112, 03192–232100, 03192–236641 तथा 03192–232400 पर उपलब्ध कराएं। सूचनादाता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

पांडुलिपियों एवं अभिलेखीय धरोहर की

पृष्ठ 1 का शेष

विवरण कला एवं संस्कृति विभाग, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन को सेल्युलर जेल परिसर स्थित कार्यालय में जाकर प्रस्तुत कर सकते हैं या दूरभाष संख्या 234775/9476037145 अथवा ईमेल **cellularjailandaman@gmail.com** एवं **artand.culture@and.nic.in** के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इस पहल में योगदान देकर नागरिक अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की समृद्ध एवं विविध विरासत को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आइए, हम सभी मिलकर अपने द्वीपों की आवाज़, स्मृतियों और इतिहास को संरक्षित करें। अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, विविध संस्कृतियों, औपनिवेशिक इतिहास, आदिवासी परंपराओं एवं समुद्री विरासत का एक अद्वितीय संगम है, जो भारत के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन द्वीपों में आदिकाल से निवास कर रहे आदिवासी समुदायों से लेकर औपनिवेशिक काल में सेल्युलर जेल की स्थापना तथा स्वतंत्रता पश्चात एक सजीव द्वीपीय समाज के विकास तक, इन द्वीपों की समृद्ध विरासत यहाँ के लोगों, परंपराओं एवं ऐतिहासिक अभिलेखों में परिलक्षित होती है। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस अमूल्य धरोहर का संरक्षण एवं प्रलेखन अत्यंत आवश्यक है, जो पांडुलिपियों, दुर्लभ पुस्तकों, व्यक्तिगत डायरी, पत्रों, छायाचित्र/नेगेटिव, मानचित्र, प्रशासनिक अभिलेखों, ऑडियो–विजुअल रिकॉर्डिंग तथा अन्य दस्तावेजों के रूप में उपलब्ध है, जो इन द्वीपों के जीवन एवं इतिहास के विभिन्न चरणों को दर्शाते हैं। व्यक्तियों, परिवारों, संस्थानों एवं संगठनों के पास उपलब्ध ये सामग्रियाँ अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के सामाजिक–सांस्कृतिक विकास, स्वतंत्रता संग्राम, प्रवासन पैटर्न एवं आदिवासी परंपराओं के महत्वपूर्ण ज्ञान–स्रोत हैं।

प्राचीन पांडुलिपियाँ एवं दुर्लभ अभिलेख हमारी बौद्धिक परंपराओं, सांस्कृतिक धरोहर एवं सामूहिक स्मृति के अमूल्य प्रमाण हैं। उनका संरक्षण एवं भावी पीढ़ियों तक हस्तांतरण हमारी साझा जिम्मेदारी है। लोगों से भारत सरकार के इस मिशन में आगे आकर योगदान देने का आह्वान किया गया है।

बौद्धिक संपदा प्रबंधन एवं व्यावसायीकरण पर कार्यशाला आयोजित

श्री विजय पुरम, 29 अप्रैल

आईसीएआर–केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर–सीआईएआरआई), श्री विजय पुरम द्वारा विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर 29 अप्रैल, 2026 को संस्थान परिसर में "आईपी और खेलः तैयार, सज्ज, नवाचार!" विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

नई दिल्ली स्थित एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डॉ. प्रवीण मलिक ने तकनीकों के लाइसेंसिंग एवं व्यावसायीकरण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रयोगशालाओं में विकसित नवाचारों को प्रभावी रूप से किसानों तक पहुंचाना आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वैज्ञानिक प्रगति को उद्योगों के साथ मजबूत साझेदारी के माध्यम से कृषि समुदाय तक हस्तांतरित किया जाना चाहिए। डॉ. मलिक ने वैज्ञानिकों को अपने–अपने विषयों के साथ–साथ अन्य संस्थानों के वैज्ञानिकों के साथ भी सहयोगात्मक रूप से कार्य करने की सलाह दी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, तकनीकों के सफल व्यावसायीकरण हेतु औद्योगिक सहयोग विकसित करने में हर संभव सहायता प्रदान करेगा।

इससे पूर्व, आईसीएआर–सीआईएआरआई के कार्यवाहक निदेशक, डॉ. जय सुंदर ने द्वीप कृषि की वर्तमान स्थिति पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने द्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्र में कृषि से जुड़ी विशिष्ट चुनौतियों एवं संभावनाओं को रेखांकित किया

तथा संस्थान द्वारा विकसित विभिन्न फसल किस्मों और नवाचारपूर्ण तकनीकों का प्रदर्शन किया, जो द्वीप के किसानों के लिए लाभकारी हैं।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस कार्यशाला में संस्थान के विभिन्न प्रभागों से लगभग 30 वैज्ञानिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रधान वैज्ञानिक एवं पीएमई प्रभारी तथा पशु विज्ञान प्रभाग की कार्यवाहक प्रमुख, डॉ. टी. सुजाता ने उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। उन्होंने कृषि अनुसंधान में बौद्धिक संपदा प्रबंधन एवं व्यावसायीकरण के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम का समापन वैज्ञानिक डॉ. डी. करुणाकरण द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। उन्होंने सभी अतिथियों, वक्ताओं एवं प्रतिभागियों के प्रति उनके मूल्यवान सहयोग और उपस्थिति के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया।

दक्षिण अण्डमान जिले में कार्यस्थल स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित

श्री विजय पुरम, 29 अप्रैल

आयुष्मान आरोग्य शिविर अभियान को सामुदायिक स्तर तक विस्तारित करने के उद्देश्य से, दक्षिण अण्डमान जिला प्रशासन द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के समन्वय में, जिले भर में व्यापक कार्यस्थल स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन प्रारंभ किया गया है।

ये स्वास्थ्य जांच शिविर विभिन्न सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठानों जैसे कार्यालयों, फर्मों, होटलों, दुकानों, निर्माण स्थलों, स्पा, कार्यशालाओं, ट्रैवल एजेंसियों तथा अन्य कार्यस्थलों पर आयोजित किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य संक्रामक एवं असंक्रामक रोगों सहित अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की शीघ्र पहचान एवं जांच सुनिश्चित करना है।

स्वास्थ्य जांच के लिए विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जुड़े विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम तैनात की जाएगी, जो स्वास्थ्य परीक्षण करने के साथ–साथ आगे की जांच एवं उपचार हेतु नमूने भी एकत्रित करेगी।

सभी सरकारी कार्यालयों के विभागाध्यक्षों तथा निजी प्रतिष्ठानों के मालिकों/प्रभारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे शिविरों के सुचारू एवं प्रभावी संचालन के लिए नामित स्वास्थ्य जांच टीमों के साथ पूर्ण सहयोग एवं समन्वय स्थापित करें।

उनसें आगे यह भी अनुरोध किया जाता है किः

- कार्यस्थल पर शिविरों के आयोजन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।
- कर्मचारियों, स्टाफ एवं श्रमिकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करें।
- आवश्यकता होने पर स्वास्थ्य टीमों के साथ समन्वय हेतु एक नोडल अधिकारी नामित करें।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार शिविरों का कार्यक्रम एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं दक्षिण अण्डमान की जिला स्वास्थ्य समिति की नामित स्वास्थ्य टीमों द्वारा सूचित एवं संचालित की जाएंगी। सहायक आयुक्त द्वारा जारी परिपत्र में यह जानकारी दी गई है।

आयुष्मान भारत–पीएमजेएवाई योजना के तहत पात्र लाभार्थियों से कार्ड बनाने की अपील

श्री विजय पुरम, 29 अप्रैल

आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी–पीएमजेएवाई) को देशव्यापी क्रियान्वयन के अनुरूप 23 सितंबर, 2018 को अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में लागू किया गया था। यह योजना प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों में द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। इससे पात्र परिवारों को वित्तीय सुरक्षा के साथ गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित होती है।

भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, द्वीप समूह में कुल 23,785 परिवार, जिनमें 89,061 लाभार्थी शामिल हैं, इस योजना के अंतर्गत पात्र के रूप में चिन्हित किए गए हैं। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी पात्र परिवार सदस्यों को अपना व्यक्तिगत आयुष्मान भारत–पीएमजेएवाई कार्ड बनवाना आवश्यक है।

संघ राज्य क्षेत्र में प्राथमिक घरेलू परिवार (पीएचएच) एवं अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) राशन कार्ड धारकों की एक बड़ी संख्या ने अभी तक अपने आयुष्मान

भारत–पीएमजेएवाई कार्ड नहीं बनवाए हैं। ऐसे लाभार्थियों से आग्रह किया गया है कि वे शीघ्र ही अपना कार्ड बनवाएं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपचार का लाभ प्राप्त कर सकें।

आयुष्मान भारत–पीएमजेएवाई कार्ड 'आयुष्मान ऐप' के माध्यम से आसानी से बनाए जा सकते हैं, जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इसके अलावा, लाभार्थी अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर या आशा, एएनएम अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) से संपर्क कर भी कार्ड बनवाने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

प्रशासन ने सभी पात्र लाभार्थियों से अपील की है कि वे बिना विलंब अपने कार्ड बनवाएं, ताकि इस महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत कोई भी पात्र व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ से वंचित न रह जाए।

नोडल अधिकारी (एबी–पीएमजेएवाई) से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सहायता या किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए लाभार्थी राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह से दूरभाष संख्या 03192–214763 पर कार्यालय समय (प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक) संपर्क कर सकते हैं।

दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी योजना पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

श्री विजय पुरम, 29 अप्रैल

समाज कल्याण निदेशालय द्वारा यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) योजना पर एक जागरूकता कार्यक्रम 29 अप्रैल, 2026 को प्रातः 9.30 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, टुसनासबाद एवं फरारगंज में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम दक्षिण अण्डमान के ग्रामीण क्षेत्रों में यूडीआईडी योजना के प्रति जागरूकता फैलाने की विशेष पहल के अंतर्गत आयोजित किया गया, ताकि इन क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजन सरकारी लाभ एवं सेवाओं का समुचित लाभ उठा सकें।

इस कार्यक्रम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, टुसनाबाद एवं फरारगंज के चिकित्सा अधिकारियों के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, चिकित्सा कर्मचारियों एवं आम जनता ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान राज्य समन्वयक (यूडीआईडी) ने यूडीआईडी प्रमाणन प्रक्रिया एवं पंजीकरण से संबंधित तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी तथा पात्र लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत पंजीकरण के लिए प्रेरित किया।

सीआरसी ब्रुक्शाबाद के संसाधन व्यक्ति ने विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं एवं चिकित्सीय मूल्यांकन प्रक्रिया पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बिस्तर पर रहने वाले दिव्यांगजनों के मूल्यांकन हेतु टेली–कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा की जानकारी भी दी तथा सीआरसी द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सहायता सेवाओं एवं लाभों को भी रेखांकित किया।

दिव्यांग प्रभारी ने दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं लाभों के बारे में जानकारी देते हुए इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए यूडीआईडी कार्ड प्राप्त करने के महत्व पर जोर दिया।

नोडल अधिकारी (यूडीआईडी) से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यूडीआईडी योजना के अंतर्गत जागरूकता बढ़ाना एवं पंजीकरण को प्रोत्साहित करना था, ताकि दिव्यांगजनों को सरकारी लाभ एवं सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित की जा सके। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसमें सभी प्रतिभागियों के सहयोग एवं सहभागिता की सराहना की गई।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) एस. बिजू पिल्लै
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

ई–निविदा सूचना (दूसरी कॉल)

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड, विकास भवन, पोस्ट बॉक्स नं.180, श्री विजय पुरम (अनिडको) की ओर से अलोनिवि या किसी अन्य सरकारी विभाग के ठेकेदारों से ऑनलाइन मद दर ई–निविदा (दूसरी कॉल) आमंत्रित की जाती है भले ही उनकी सूची इस शर्ते पर हो कि उन्हें सीपीडब्ल्यूडी वर्कस मैनुअल के अनुसार और इन द्वीपों में अन्य भारत सरकार संगठनों के साथ कार्य के प्रासंगिक परिमाण को क्रियान्वित करने का अनुभव है और उनके पास कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है :

एन.आई.टी.सं. अनिडको/सीडब्लू/25–26/टीडी–29

कार्य का नामः सुभाषग्राम, डिगलीपुर में दुग्ध शीतलन केंद्र की मरम्मत और रख–रखाव।

अनुमानित लागत : रु. 4,57,157/–

निविदा/बोली प्रसंस्करण शुल्क : लागू नहीं

बयाना राशि : रु. 9,145/–

कार्य पूर्ण करने की अवधि : 30 दिन

निविदा दस्तावेज प्रकाशन तिथि : 29.04.2026

निविदा दस्तावेज डाउनलोड/आरंभ तिथि : 29/04/2026 के अपराह्न 3.00 बजे

निविदा दस्तावेज जमा करने की आरंभ तिथि : 05/05/2026 के पूर्वाह्न 10.00 बजे

निविदा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि : 13/05/2026 के अपराह्न 3.00 बजे तक

निविदा खोलने की तिथि : 14/05/2026 के पूर्वाह्न 11.00 बजे

निविदा प्रपत्र एवं अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।

निविदा आईडी 2026_ANCVL_22542_2

महाप्रबंधक (सिविल कार्य), अनिडको

ई–निविदा सूचना (दूसरी कॉल)

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड, विकास भवन, पोस्ट बॉक्स नं.180, श्री विजय पुरम (अनिडको) की ओर से अलोनिवि या किसी अन्य सरकारी विभाग के ठेकेदारों से ऑनलाइन मद दर ई–निविदाएं (दूसरी कॉल) आमंत्रित की जाती है भले ही उनकी सूची इस शर्ते पर हो कि उन्हें सीपीडब्ल्यूडी वर्कस मैनुअल के अनुसार और इन द्वीपों में अन्य भारत सरकार संगठनों के साथ कार्य के प्रासंगिक परिमाण को क्रियान्वित करने का अनुभव है और उनके पास कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है :

एन.आई.टी.सं. अनिडको/सीडब्लू/25–26/टीडी–30

कार्य का नामः नबाग्राम, डिगलीपुर में दुग्ध शीतलन केंद्र की मरम्मत और रखरखाव।

अनुमानित लागत : रु. 2,86,931/–

निविदा/बोली प्रसंस्करण शुल्क : लागू नहीं

बयाना राशि : रु. 5,740/–

कार्य पूर्ण करने की अवधि : 30 दिन

निविदा दस्तावेज प्रकाशन तिथि : 29/04/2026

निविदा दस्तावेज डाउनलोड/आरंभ तिथि : 29/04/2026 के अपराह्न 3.00 बजे

निविदा दस्तावेज जमा करने की आरंभ तिथि : 05/05/2026 के पूर्वाह्न 10.00 बजे

निविदा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि : 13/05/2026 के अपराह्न 3.00 बजे तक

निविदा खोलने की तिथि : 14/05/2026 के पूर्वाह्न 11.15 बजे

निविदा प्रपत्र एवं अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।

निविदा आईडी 2026_ANCVL_22543_2

महाप्रबंधक (सिविल कार्य), अनिडको

ई–निविदा सूचना (दूसरी कॉल)

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड, विकास भवन, पोस्ट बॉक्स नं.180, श्री विजय पुरम (अनिडको) की ओर से अलोनिवि या किसी अन्य सरकारी विभाग के ठेकेदारों से ऑनलाइन मद दर ई–निविदा (दूसरी कॉल) आमंत्रित की जाती है भले ही उनकी सूची इस शर्ते पर हो कि उन्हें सीपीडब्ल्यूडी वर्कस मैनुअल के अनुसार और इन द्वीपों में अन्य भारत सरकार के संगठनों के साथ कार्य के प्रासंगिक परिमाण को क्रियान्वित करने का अनुभव है और उनके पास कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है :

एन.आई.टी.सं. अनिडको/सीडब्लू/25–26/टीडी–31

कार्य का नामः टुगापुर, मायाबंदर में दुग्ध शीतलन केंद्र की मरम्मत और रख–रखाव।

अनुमानित लागत : रु. 4,28,172/–

निविदा/बोली प्रसंस्करण शुल्क : लागू नहीं

बयाना राशि : रु. 8,565/–

कार्य पूर्ण करने की अवधि : 30 दिन

निविदा दस्तावेज प्रकाशन तिथि : 29/04/2026

निविदा दस्तावेज डाउनलोड/आरंभ तिथि : 29/04/2026 के अपराह्न 3.00 बजे

निविदा दस्तावेज जमा करने की आरंभ तिथि : 05/05/2026 के पूर्वाह्न 10.00 बजे

निविदा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि : 13/05/2026 के अपराह्न 3.00 बजे तक

निविदा खोलने की तिथि : 14/05/2026 के पूर्वाह्न 11.30 बजे

निविदा प्रपत्र एवं अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।

निविदा आईडी 2026_ANCVL_22544_2

महाप्रबंधक (सिविल कार्य), अनिडको

ई–निविदा सूचना

कार्यपालक अभियंता, पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान, प्रमुख, पंचायत समिति, प्रात्रापुर की ओर से, निम्नलिखित कार्यों के लिए उचित श्रेणी के योग्य व अनुभवी ठेकेदारो से मुहरबंद मद दर (के.लो.नि.वि.–8 के प्रपत्र के रूप में) आमंत्रित करते है।

एन. आई. टी. संख्या : क.अ./पी आर आई/एस ए डी–।/आर आर (जीईएन)/2026–27/11

कार्य का नाम : प्रात्रापुर पंचायत समिति द्वारा न्यू बिम्बलिटान 04 में मुख्य सड़क न्यू बिम्बलिटान से चर्च तक ग्रामीण सड़क की मरम्मत और रखरखाव।

अनुमानित लागत : रु. 13,23,262/–, धरोहर राशि : रु. 26,465/–, कार्य समाप्ति की अवधि : (06) छह माह।

निविदा शुल्क : रु. 500/–, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 05/05/2026 के सायं 3.00 बजे तक।

निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।

टेंडर आई डी : 2026_RDPRI_22831_1

कार्यपालक अभियंता,
पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।,
जंगलीघाट, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान

शुद्धि पत्र

सं. एएलएचडब्ल्यू/टेक/टीईसीएल (टेंड)/1/2026/ई–2960/872 दिनांक 28.04.2026

कार्य का नाम :– "अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में कार निकोबार के मूस में समुद्री दीवार/तटीय संरक्षण कार्य (450 मीटर) का निर्माण"।

एनआईटी सं. दिनांक 25.03.2026 के पत्र सं.सं. एएलएचडब्ल्यू/ टेंड–कॉल/टी–02/2025–26/रे–कॉल

विषय से संबंधित उपरोक्त एनआईटी के संदर्भ में, निम्नलिखित शुद्धिपत्र जारी किया जाता है।

खंड 1.3 : आरएफपी दस्तावेज की बोली प्रक्रिया का कार्यक्रम

क्र. सं.	विवरण	निविदा दस्तावेज के अनुसार तिथि	दिनांक के रूप में संशोधित
1	बोली की नियत तिथि	28.04.2026 दोपहर 1500 बजे तक	06.05.2026 दोपहर 1500 बजे तक
2	मूल बोली सुरक्षा की भौतिक प्रस्तुति	तकनीकी निविदा खुलने की तिथि पर या उससे पहले (29.04.2026 को 1530 बजे तक)	तकनीकी निविदा खुलने की तिथि पर या उससे पहले (12.05.2026 को दोपहर 1530 बजे तक)
3	धारा 2.15.3 के अनुसार निर्धारित स्थल पर तकनीकी बोलियां खोली जाएंगी।	29.04.2026 को 1530 बजे।	12.05.2026 दोपहर 1530 बजे तक

एनआईटी में दिए गए अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

उप मुख्य अभियंता (नौसेना परियोजना)
अलबस, श्री विजय पुरम

शपथ पत्र

मैं, ए. नवीन, पुत्र श्री जी. अरुमुगम, निवासी हैड्डो, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान जिला, विधिवत शपथ लेकर निम्नलिखित घोषणा करता हूँ :

1. कि मैं इस शपथ पत्र का शपथकर्ता हूँ तथा नीचे दिए गए तथ्यों से भली–भांति परिचित हूँ।
2. कि मेरी सही जन्म तिथि 25/04/2005 है।
3. कि अनजाने में/लिपिकीय त्रुटि के कारण मेरी जन्म तिथि मेरे जन्म प्रमाण पत्र (पंजीकरण संख्या 1052) में 24/05/2005 दर्ज हो गई है, जो कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है।
4. कि मेरी सही जन्म तिथि 25/04/2005 मेरे अन्य दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड द्वारा प्रमाणित है।
5. कि मैं संबंधित प्राधिकारी से अनुरोध करता हूँ कि मेरे जन्म प्रमाण पत्र में मेरी जन्म तिथि को सही कर 25/04/2005 दर्ज किया जाए तथा संशोधित प्रमाण पत्र जारी किया जाए।
6. कि यह शपथ पत्र मैं अपनी सही जन्म तिथि घोषित करने एवं संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु बना रहा हूँ।

स्थान : श्री विजय पुरम

शपथकर्त्ता

भारत–केन्या संयुक्त व्यापार समिति की बैठक

नई दिल्ली, 29 अप्रैल।

भारतदृकेन्या संयुक्त व्यापार समिति की 10वीं बैठक नैरोबी में आयोजित की गई, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया गया। केन्या के लिए भारत एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है, जबकि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़कर 4.31 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में बताया कि भारत–केन्या के बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। भारत और केन्या संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) का 10वां सत्र 27–28 अप्रैल को नैरोबी में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग की समीक्षा करना और उसे सुदृढ़ बनाना था। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार में लगातार वृद्धि का उल्लेख किया, जिसमें भारत केन्या के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक के रूप में उभरा है। भारत और केन्या के बीच वित्त वर्ष 2025–26 में कुल व्यापार 4.31 अरब अमेरिकी डॉलर रहा है, जो वित्त वर्ष 2024–25 के 3. 45 अरब अमेरिकी डॉलर से 24.91 फीसदी की वृद्धि है।

चारधाम यात्रा–दस दिन में चार लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

देहरादून, 29 अप्रैल।

प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारु रूप से चल रही है। राज्य सरकार ने यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। कपाट खुलने से लेकर 28 अप्रैल, 2026 की सायं 7 बजे तक मात्र दस दिन में कुल 4 लाख 8 हजार 401 श्रद्धालु चारो धामों में दर्शन के लिए पहुंचे हैं।

चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों, श्रद्धालुओं एवं स्थानीय नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए चारधाम यात्रा मार्गों सहित प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर पेयजल, शौचालय, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, पार्किंग एवं यातायात व्यवस्थाओं को सुदृढ़ एवं व्यवस्थित किया गया है। राज्य सरकार ने यात्रा व्यवस्थाओं के संबंध में भ्रामक जानकारी प्रसारित करने वालों तथा गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, ताकि यात्रा की पवित्रता एवं व्यवस्थाएं बनी रहें। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र, देहरादून से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार चारधाम कपाट खुलने से 28 अप्रैल, 2026 की सांय 7 बजे तक मात्र दस दिनों में कुल 4 लाख 8 हजार 401 श्रद्धालु चारधाम में दर्शन के लिए पहुंचे हैं।

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार अब तक यमुनोत्री धाम में 57,794, गंगोत्री में 57,863, केदारनाथ धाम में 2,07,452 और बदरीनाथ धाम में 84,942 श्रद्धालु ने दर्शन कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त गौमुख में अब तक 440 यात्री पहुंचे हैं। वर्तमान यात्रा सीजन में अब तक कुल 64,115 वाहन यात्रियों को लेकर चारधाम पहुंचे हैं। राज्य सरकार ने सभी संबंधित विभागों के समन्वय से यात्रा को सुरक्षित, सुगम एवं व्यवस्थित बनाने के निर्देश दिए हैं।

सीडीएस की इंग्लैंड यात्राः आरएएफ वैली में तैनात होंगे भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर

नई दिल्ली, 29 अप्रैल।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान बीते दिनों ब्रिटेन की आधिकारिक यात्रा पर थे। यह भारतीय सीडीएस की पहली आधिकारिक ब्रिटेन यात्रा थी। इस यात्रा को दोनों देशों के रक्षा संबंधों में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों ने इसे ब्रिटेन और भारत के बीच रक्षा सहयोग में एक अहम कदम बताया है।

19 से 21 अप्रैल की तीन दिवसीय इस यात्रा में जनरल चौहान ने ब्रिटेन के शीर्ष सैन्य नेतृत्व के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकें की। ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एयर चीफ मार्शल सर रिचर्ड नाइटन ने यहां उनका स्वागत व मेजबानी की। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, रणनीतिक साझेदारी और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा हुई।

इस यात्रा के दौरान जनरल चौहान ने ब्रिटेन के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, मंत्रियों, शिक्षाविदों और थिंक टैंकों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। इसके अलावा ब्रिटिश रक्षा उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत हुई, जिसमें रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, रोजगार के अवसर सृजित करने और आर्थिक विकास को गति देने जैसे मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया। दोनों देशों ने इस बात पर जोर दिया कि रक्षा सहयोग न केवल सुरक्षा को मजबूत करता है, बल्कि आर्थिक साझेदारी को भी बढ़ावा देता है।

जनरल चौहान ने इस दौरान प्रतिष्ठित रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज का भी दौरा किया। वहां उन्होंने ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम और पिनेकल कोर्स के अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों से मुलाकात की। ये कार्यक्रम भविष्य के वरिष्ठ सैन्य और सरकारी नेतृत्व को तैयार करने के लिए जाने जाते हैं। इस संवाद के जरिए भारत ने अपने रणनीतिक दृष्टिकोण और वैश्विक सुरक्षा पर विचार साझा किए।

गौरतलब है कि भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों देशों के बीच 10 साल का रक्षा औद्योगिक रोडमैप पहले ही तैयार किया जा चुका है। यह रोडमैप भविष्य में सहयोग के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। एक और महत्वपूर्ण पहल के तहत भारतीय सैन्य प्रशिक्षक पहले से ही ब्रिटेन की तीनों अधिकारी प्रशिक्षण अकादमियों में तैनात हैं।

वहीं आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग प्रशिक्षकों को ब्रिटेन के आरएएफ वैली में तैनात किया जाएगा। यह कदम दोनों देशों के बीच सैन्य प्रशिक्षण और आपसी समझ को और मजबूत करेगा। आज के जटिल वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारत और ब्रिटेन के बीच यह बढ़ता रक्षा सहयोग बेहद अहम माना जा रहा है। दोनों देश मिलकर न केवल अपनी सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता में भी महत्वपूर्ण योगदान देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

भारत ने 2014 के बाद डॉप्लर मौसम रडार नेटवर्क का व्यापक विस्तार किया

नई दिल्ली, 29 अप्रैल।

भारत ने 2014 के बाद से अपने डॉप्लर मौसम रडार नेटवर्क का व्यापक विस्तार किया है। परिचालन इकाइयों की संख्या 14 से बढ़कर 50 हो गई है, जो 250 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शाती है। यह बात विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के मौसम भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। मीडिया से बात करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत की मौसम विज्ञान सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा इस क्षेत्र को दी गई उच्च प्राथमिकता के कारण यह परिवर्तन संभव हुआ है, जिससे पूर्वानुमानों में अधिक सटीकता, सुलभता और जनता का विश्वास बढ़ा है।

डॉ. सिंह ने कहा कि यह प्रणाली आज अत्यधिक विश्वसनीय और सटीक पूर्वानुमान प्रदान करती है, जिनका उपयोग किसानों, गृहिणियों, पायलटों और इवेंट प्लानर्स सहित उपयोगकर्ताओं के एक व्यापक वर्ग द्वारा किया जाता है। पूर्वानुमान में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए, उन्होंने नाउकास्ट सेवाओं की शुरुआत पर प्रकाश डाला, जो अत्यधिक स्थानीयकृत और सटीक पूर्वानुमान प्रदान करती हैं।

इतिहास के पन्नों में 30 अप्रैलः हिटलर के अंत के साथ खत्म हुआ एक क्रूर अध्याय

नई दिल्ली, 29 अप्रैल।

इतिहास में 30 अप्रैल की तारीख एक अहम और भयावह मोड़ के रूप में दर्ज है। इसी दिन 1945 में जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में आत्महत्या कर ली थी।

बताया जाता है कि जब सोवियत सेना बर्लिन को चारों ओर से घेर चुकी थी, तब हिटलर ने अपने भूमिगत बंकर में खुद को गोली मार ली। उनके साथ उनकी पत्नी इवा ब्राउन ने भी आत्महत्या कर ली। यह बंकर जमीन से करीब 50 फीट नीचे स्थित था, जहां हिटलर ने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की नीतियों ने दुनिया को गहरे संकट में डाल दिया था। विशेष रूप से यहूदियों के खिलाफ चलाए गए उनके नरसंहार अभियान ने मानव इतिहास पर अमिट काला धब्बा छोड़ा।

हिटलर की मौत के साथ ही नाजी शासन का अंत तेजी से करीब आ गया और यूरोप में युद्ध समाप्ति की प्रक्रिया शुरू हुई। 30 अप्रैल का दिन आज भी इस बात की याद दिलाता है कि सत्ता का दुरुपयोग और कट्टर विचारधारा किस तरह पूरी दुनिया को विनाश की ओर धकेल सकती है।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र–1598 – अमेरिका में पहली बार थियेटर का आयोजन।

1789– जॉर्ज वॉशिंगटन सर्वसम्मति से अमेरिका के पहले राष्ट्रपति चुने गए।

1908– खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड के मजिस्ट्रेट की हत्या करने के लिए बम फेंका, लेकिन दो बेगुनाह बम की चपेट में आकर मारे गए।

1973– अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने देश के राष्ट्रपति के नाते वॉटरगेट कांड की ज़िम्मेदारी ली हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वह निजी तौर पर इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

1975– वियतनाम युद्ध का अंत हुआ। तीन दिन के सत्तारूढ़ राष्ट्रपति दुओंग वैन मिन्ह ने अपनी सेनाओं से समर्पण करने और उत्तरी वियतनामियों से हमले रोकने को कहा।

985 – अमेरिकी पर्वतारोही रिचर्ड डिक बास (55 वर्ष) माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक उम्र में चढ़ने वाले व्यक्ति बने।

1991 – बांग्लादेश में भीषण चक्रवात में सवा लाख से अधिक लोगों की मौत और 90 लाख लोग बेघर।

1991 – अंडमान द्वीप समूह के एक निर्जन द्वीप पर एक सुप्त पड़े ज्वालामुखी में विस्फोट। शताब्दी में पहली बार ऐसा हुआ।

1993 – जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में एक मैच के दौरान तत्कालीन वर्ल्ड नंबर एक टेनिस खिलाड़ी मोनिका सेलेज को चाकू मारकर घायल किया गया।

1999 – लेविंस्की–क्लिंटन मामले को दुनिया के सामने लाने वाले पत्रकार माइकल इशिकॉफ को अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका न्यूज वीक का श्नेशनल मैंगनीज अवार्डश प्रदान किया गया।

1999 – हिन्द महासागर के द्वीप कोमोरोस में सेना द्वारा सत्ता पर कब्जा।

2000 – आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग के आहवान के साथ जी –77 शिखर सम्मेलन हवाना में सम्पन्न।

2001 – फिलीपींस में एरुत्रादा समर्थकों द्वारा तख्ता पलट का प्रयास।

2002 – पाकिस्तान में राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ़ के अगले 5 वर्षों के कार्यकाल में वृद्धि के लिए जनमत संग्रह सम्पन्न।

बिना तनाव के बेचैनी, घबराहट और दिल जोर से धड़कना, पेट से जुड़ा है कनेक्शन

नई दिल्ली, 29 अप्रैल।

अगर अचानक बिना तनाव के बेचैनी, घबराहट और दिल जोर से धड़कने लगता है, तो यह किसी तरह के स्ट्रेस की वजह से नहीं, बल्कि पेट में हो रही गड़बड़ी के कारण हो सकता है।

आम तौर पर दिल में होने वाली बेचैनी को लोग तनाव या हृदय रोगों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर पेट के पाचन में परेशानी होती है, तो उसका असर हृदय पर भी देखने को मिलता है।

जब पाचन ठीक नहीं होता, गैस बनती है, पेट में भारीपन रहता है, तो उसका असर सीधे मन और दिल की धड़कन पर पड़ सकता है। इसलिए बार–बार घबराहट, गैस, अपच, कब्ज या पेट फूलने की समस्या को नजरअंदाज न करें। आयुर्वेद में पेट का संबंध मन से होता है। अगर पेट खराब है तो मन भी खराब होगा। जब पेट में पाचन की परेशानी के कारण गैस बनती है, तो उसका दबाव पेट पर पड़ता है और गैस सिर की तरह जाने लगती है। इससे कई बार सीने में जलन और दर्द की शिकायत भी होती है, जिसे लोग हार्ट अटैक मानकर घबरा जाते हैं, लेकिन यह खराब पाचन का संकेत है। इससे घबराहट और बेचैनी दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

इसके साथ ही अगर बार–बार गैस बनने की परेशानी, खट्टी डकार या सिर्फ कब्ज की परेशानी होती है, तो यह शरीर में आम (टॉक्सिन) बनने का संकेत हैं। जब शरीर में टॉक्सिन की समस्या बढ़ जाती है तो कब्ज और पाचन के विकार जल्दी–जल्दी होने लगते हैं और ऐसे में शुद्धिकरण बहुत जरूरी है।

यह समस्या उन लोगों में देखी जाती है, जो देर रात खाना खाते हैं, खाने के बाद टहलने की बजाय एक जगह बैठ जाते हैं, फिर ज्यादा तला और भुना खाते हैं, अधिक तनाव लेते हैं, और जिनका पेट साफ नहीं होता। यह सभी पाचन को मंद भी कर देते हैं। इससे बचने के लिए हमेशा समय पर खाना खाएं और खाने के बाद टहलें जरूर। देर रात खाना खाने से बचना चाहिए। अगर पेट साफ नहीं होता है तो रात को सौंफ और मिश्री का सेवन जरूर करें। अगर पेट साफ रहेगा तो शरीर में टॉक्सिन की परेशानी नहीं होगी।

न्यूजीलैंड के लिए भारत के साथ आगे बढ़ने का बहुत बड़ा मौका है: एफटीए डील पर बोले प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन

नई दिल्ली, 29 अप्रैल।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। एफटीए को लेकर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि ये डील न्यूजीलैंड के लिए पीढ़ी में एक बार मिलने वाला मौका है। न्यूजीलैंड के लिए भारत के साथ आगे बढ़ने का बहुत बड़ा मौका है। 27 अप्रैल को दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे न्यूजीलैंड को होने वाले भारत के 100 फीसदी निर्यात पर टैरिफ की छूट मिलेगी। वहीं न्यूजीलैंड से भारत आने वाले 95 फीसदी सामान पर टैरिफ की छूट होगी।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी कर पीएम लक्सन ने कहा, आपने शायद वीकेंड में भारत में इंडियन एफटीए साइन होने के बारे में सुना होगा और यह बहुत अच्छी खबर है क्योंकि यह न्यूजीलैंड के लिए पीढ़ी में एक बार मिलने वाला मौका है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारत अब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। देश में लगभग डेढ़ अरब लोग रहते हैं। वे तेजी से अमीर होते जा रहे हैं और इसलिए वे न्यूजीलैंड जैसी जगहों से बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट और सर्विस लेना चाहते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनना जा रहा है।

उन्होंने कहा, न्यूजीलैंड के लिए भारत के साथ आगे बढ़ने का बहुत बड़ा मौका है क्योंकि भारत लो–इनकम से मिडिल–इनकम की ओर बढ़ रहा है और न्यूजीलैंड के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की ज्यादा डिमांड कर रहा है। हम भारत को जो लगभग 95 फीसदी सामान एक्सपोर्ट करते हैं, अच्छी खबर यह है कि पहले दिन से ही, 57 फीसदी टैरिफ–फ्री है और एग्रीमेंट के दौरान यह बढ़ता जाएगा। जैसे–जैसे भारतीय बाजार बढ़ेगा, हम दुनिया भर के प्रोडक्ट्स से मुकाबला कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कीवी लोगों की जेब में ज्यादा पैसा, ज्यादा इनकम और भारत में तेजी से बढ़ने की वजह से ज्यादा नौकरियां।

इस समझौते के तहत भारत को सभी टैरिफ उत्पादों पर

तत्काल 100 प्रतिशत शुल्क–मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। यह न्यूजीलैंड द्वारा वर्तमान में भारत से निर्यात किए जाने वाले लगभग 450 टैरिफ उत्पादों पर लगाए जाने वाले 10 प्रतिशत शुल्क से कम है, जिनमें वस्त्र और परिधान उत्पाद, चमड़ा और टोपी, चीनी मिट्टी के बर्तन, कालीन और वाहन एवं वाहन पुर्जे शामिल हैं।

इस मुक्त व्यापार समझौते में एक प्रावधान यह भी है कि न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब डॉलर का निवेश करेगा। इसके अलावा, इस एफटीए में कामकाजी पेशेवरों और छात्रों की आवाजाही से संबंधित कई प्रावधान शामिल हैं। न्यूजीलैंड ने किसी भी देश के साथ पहली बार छात्र आवाजाही और अध्ययन के बाद कार्य वीजा संबंधी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत, भारतीय छात्र न्यूजीलैंड में पढ़ाई के दौरान विस्तारित अध्ययन के बाद कार्य वीजा के साथ प्रति सप्ताह 20 घंटे तक काम कर सकते हैं।

एफटीए में भारतीय पेशेवरों को भी उच्च वेतन वाले रोजगार के अवसर खुलेंगे। समझौते के तहत, न्यूजीलैंड कौशल युक्त भारतीय पेशेवरों को एक अस्थायी रोजगार वीजा देगा, जिसके तहत पेशेवर न्यूजीलैंड में तीन साल तक रहकर कार्य कर सकेंगे। हालांकि, यह कोटा 5,000 वीजा का निर्धारित किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने आरटीई के तहत अनिवार्य दाखिले को बरकरार रखा

नई दिल्ली, 29 अप्रैल।

सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत, विद्यार्थियों के अनिवार्य दाखिले को राष्ट्रीय मिशन बताते हुए बरकरार रखा है। न्यायालय ने आज कहा कि निजी गैर–सहायता प्राप्त संस्थानों सहित स्थानीय विद्यालय, पात्र विद्यार्थियों को बिना किसी देरी के दाखिला देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने कहा कि कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों को विद्यालयों में दाखिला ना देना, संविधान के अनुच्छेद 21–अ के तहत शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

न्यायालय ने कहा कि शिक्षा के अधिकार के तहत ऐसे विद्यार्थियों के लिए तय, 25 प्रतिशत आरक्षण में, सामाजिक संरचना को सकारात्मक रूप से बदलने और समानता की भावना को बढ़ावा देने की क्षमता है। न्यायालय ने कहा कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून का प्रभावी कार्यान्वयन आवश्यक है।

सर्वोच्च न्यायालय ने लखनऊ के एक निजी स्कूल की याचिका को खारिज किया। स्कूल ने शिक्षा के अधिकार

कानून के तहत पात्र एक छात्रा को प्रवेश देने से इनकार किया था। उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए, पीठ ने कहा कि विद्यालय, सरकारी अधिकारियों द्वारा लिए गए पात्रता निर्णयों पर सवाल नहीं उठा सकते और ना ही उन्हें, रद्द कर सकते। न्यायालय ने कहा कि एक बार राज्य द्वारा चयनित विद्यार्थियों की सूची भेजे जाने के बाद, विद्यालयों के पास प्रवेश देने के अलावा कोई विकल्प है। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में किसी तरह रूकावट शिक्षा के अधिकार को एक खोखला वादा बना देगी।

ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग और डिलीवरी प्रमाणीकरण कोड आधारित आपूर्ति रिकॉर्ड स्तर पर–पेट्रोलियम मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 अप्रैल।

पश्चिम एशिया में चल रही बदलती स्थिति के बावजूद, सरकार ने आज आश्वासन दिया कि देश भर में घरेलू एलपीजी आपूर्ति बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से जारी है। नई दिल्ली में आयोजित एक अंतर–मंत्रालयी समीक्षा की जानकारी हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में एलपीजी वितरकों के यहां एलपीजी की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग और डिलीवरी प्रमाणीकरण कोड आधारित घरेलू एलपीजी आपूर्ति भी अब तक के सबसे उच्च स्तर पर है। सुश्री शर्मा ने बताया कि देश भर में वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति 70 प्रतिशत तक बहाल हो चुकी है और अप्रैल माह में एक लाख 84 हजार टन से अधिक वाणिज्यिक एलपीजी की बिक्री हुई है। उन्होंने कहा कि कल तक 8 हजार 838 टन से अधिक वाणिज्यिक एलपीजी की बिक्री हुई। सचिव ने आगे बताया कि 5 किलो के सिलेंडरों की आपूर्ति लगभग दोगुनी हो गई है और कल लगभग 73 हजार सिलेंडर बिके।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि सभी भारतीय बंदरगाहों पर परिचालन सामान्य है और किसी भी प्रकार की भीड़भाड़ की सूचना नहीं मिली है। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्र में

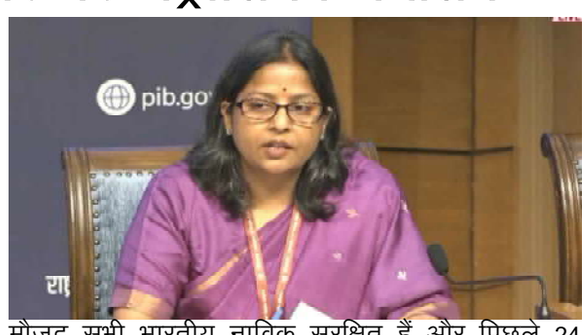

मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटों में किसी भी भारतीय ध्वज वाले जहाज से संबंधित कोई घटना दर्ज नहीं की गई है। श्री मंगल ने रेखांकित किया कि जहाजरानी महानिदेशालय के नियंत्रण के माध्यम से मंत्रालय ने 2 हजार 829 भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की है। उन्होंने आगे बताया कि पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सरबानंदा सोनोवाल ने हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, उर्वरक विभाग और विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ होर्मुज जलडमरूमध्य से संबंधित मुद्दों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि मंत्री ने समुद्री परिचालन और जहाजरानी के माध्यम से आयात और निर्यात गतिविधियों के सुचारू रूप से चलने को सुनिश्चित करने के उपायों की भी समीक्षा की।

आरबीआई ने शहरी को–ऑपरेटिव बैंकों को मजबूत बनाने के लिए लॉन्च किया 'मिशन सक्षम'

नई दिल्ली, 29 अप्रैल।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को शहरी को–ऑपरेटिव बैंकों यानी सहकारी बैंकिंग (यूसीबी) सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए शमिशन सक्षमश (सहकारी बैंक क्षमता निर्माण) की शुरुआत की है। यह पूरे देश में लागू होने वाला एक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य को–ऑपरेटिव बैंकों की कार्यक्षमता और प्रबंधन को बेहतर बनाना है।

केंद्रीय बैंक ने एक नोट में बताया कि आरबीआई द्वारा शुरू किए गए इस मिशन के तहत करीब 1.40 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें बैंक के बोर्ड मेंबर्स, सीनियर मैनेजमेंट, रिस्क, कंप्लायंस और ऑडिट विभाग के प्रमुखों के साथ–साथ आईटी और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा।

यह ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफलाइन (इन–पर्सन) और ऑनलाइन (ई–लर्निंग) दोनों माध्यमों से आयोजित किए जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाई जा सके। सक्षम का मतलब है–काबिल और सक्षम बनाना। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराए जाएं, ताकि अलग–अलग राज्यों के कर्मचारियों को समझने में आसानी हो।

इस मिशन को तैयार करने में यूसीबी सेक्टर की अंब्रेला संस्था और राष्ट्रीय/राज्य सहकारी संघों से भी सलाह ली गई है। आरबीआई का मानना है कि इस पहल से सहकारी बैंकों की मैनेजमेंट क्षमता और ऑपरेशनल दक्षता में सुधार होगा। साथ ही, नियमों के पालन की संस्कृति मजबूत होगी और बैंकों की संस्थागत मजबूती भी बढ़ेगी। नोट में कहा है कि यह मिशन एक ऐसा सिस्टम तैयार करने की दिशा में काम करेगा, जहां लगातार सीखने और सुधार की प्रक्रिया बनी रहे।

मिशन सक्षम के जरिए आरबीआई का लक्ष्य सिर्फ ट्रेनिंग देना ही नहीं, बल्कि एक स्थायी और मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना है, जिससे पूरे यूसीबी सेक्टर की स्थिरता और विकास को गति मिले। केंद्रीय बैंक का कहना है कि यह पहल सहकारी बैंकों के भविष्य को और सुरक्षित और मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।

देश में इलाज का खर्च हुआ कम, एनएसओ सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी

नई दिल्ली, 29 अप्रैल।

देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है और लोगों के पॉकेट पर इलाज के खर्च का दवाब भी कम हुआ है। बुधवार को जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के 80वें दौर के सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह तथ्य उजागर हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच पहले के मुकाबले काफी बेहतर हुई है और इलाज का खर्च भी कम हुआ है।

रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी अस्पतालों में मरीजों का खर्च काफी कम हो गया है। आधे से ज्यादा भर्ती मामलों में मरीजों को औसतन सिर्फ 1100 रुपये ही अपनी जेब से खर्च करना पड़ा। वहीं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में बाह्य रोगी (ओपीडी) सेवाएं कई जगह पूरी तरह मुफ्त मिल रही हैं, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। सर्वे में यह भी सामने आया है कि अब लोग पहले की तुलना में ज्यादा इलाज के लिए आगे आ रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में बीमार होने की रिपोर्ट करने वाले लोगों का प्रतिशत 6.8 से बढ़कर 12.2 प्रतिशत हो गया है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 9.1 प्रतिशत से बढ़कर 14.9 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

ग्रामीण भारत में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का इस्तेमाल भी बढ़ा है। ओपीडी सेवाओं के लिए सरकारी अस्पतालों का उपयोग 2014 के 28 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 35 प्रतिशत हो गया है।

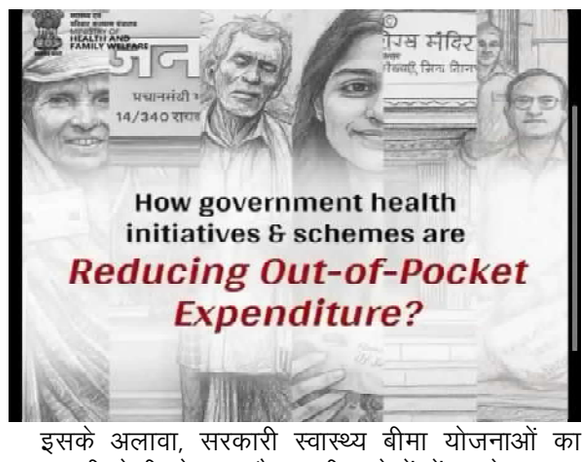

इसके अलावा, सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का दायरा भी तेजी से बढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कवरेज 12.9 प्रतिशत से बढ़कर 45.5 प्रतिशत हो गया है, जबकि शहरी इलाकों में यह 8.9 प्रतिशत से बढ़कर 31.8 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि गरीब वर्गों पर इलाज का खर्च कम हुआ है, जिससे यह साफ है कि सरकारी योजनाओं का असर जमीनी स्तर पर दिख रहा है।

मातृ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति दर्ज की गई है। संस्थागत प्रसव अब ग्रामीण क्षेत्रों में 95.6 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 97.8 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय आज से चंडीगढ़ में 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा

नई दिल्ली, 29 अप्रैल। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कल से चंडीगढ़ में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में बेहतर और अनुकरणीय प्रथाओं तथा नवाचारों पर 10वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाई गई नवोन्मेषी और प्रभावशाली प्रथाओं को प्रदर्शित करना, उन्हें मान्यता देना और उनका दस्तावेजीकरण करना है। यह सम्मेलन अनुभव साझा करने और सफल मॉडलों को देश भर में लागू करने का अवसर प्रदान करेगा। वार्षिक शिखर सम्मेलन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण और तकनीकी क्षेत्रों में ऐसे साक्ष्य–आधारित और प्रभावी नवाचारों को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है, जिनसे स्वास्थ्य परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। सम्मेलन में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर बनाने, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचारों और सेवा वितरण प्रणालियों में सुधार जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर पूर्ण सत्र, चर्चाएँ और प्रदर्शनियाँ आयोजित होंगी।

ये है हकीकत: समंदर के बीचों–बीच पैदल चलते हैं लोग, साल में 2 बार ही मिलता है मौका

नई दिल्ली, 29 अप्रैल।

जरा सोचिए, आप लहरों से भरे विशाल समुद्र के बीचों–बीच टहल रहे हों। पढ़ने में यह किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन लग सकता है, लेकिन साउथ कोरिया में कुदरत सच में कुछ ऐसा ही कमाल दिखाती है। जी हां, यहां के जिंदो द्वीप पर समुद्र का पानी अचानक से पीछे खिसक जाता है और लहरों के बीच से एक लंबी, सूखी राह उभर आती है। 'Jindo Miracle' के नाम से मशहूर यह रास्ता जिंदो द्वीप को पास के मोटो और सेओडो द्वीपों से जोड़ देता है।

प्रकृति का यह जादुई शो हमेशा के लिए नहीं रुकता। समंदर के बीच बनी यह सड़क महज 40 से 60 मिनट तक ही दिखाई देती है। एक घंटे से भी कम समय में पानी की लहरें दोबारा लौट आती हैं और यह रास्ता हमेशा–हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इसलिए, इस रोमांचक पल का गवाह बनने के लिए सही समय पर वहां मौजूद होना बहुत जरूरी है, और यही वजह है कि इसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है।

भले ही लोग इसे चमत्कार मानते हों, लेकिन असल में इसके पीछे पूरी तरह से विज्ञान छिपा है। यह सब समुद्र के ज्वार–भाटे के कारण होता है। जब सूरज और चांद एक विशेष स्थिति में आते हैं, तो उनके खिंचाव से पानी तेजी से पीछे की तरफ चला जाता है। इसके साथ ही, जिंदो द्वीप की भौगोलिक बनावट भी कुछ इस तरह की है कि पानी के हटते ही समुद्र की सतह एक सड़क की तरह ऊपर उभर कर आ जाती है।

यह अनोखी घटना दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती है और साल में सिर्फ दो बार ही होती है– एक बार वसंत (मार्च–अप्रैल) में और दूसरी बार पतझड़ यानी सितंबर–अक्तूबर के महीने में। इस दौरान पूरा इलाका एक उत्सव में बदल जाता है और यहां 'जिंदो मिरेकल फेस्टिवल' मनाया जाता है।

समुद्र के बीच चलते हुए लोग अपने कैमरों में इस नजारे को कैद करते हैं। रास्ते में आम दिनों में पानी के नीचे छिपे रहने वाले शंख, सीपियां और समुद्री जीव भी देखने को मिलते हैं। स्थानीय नाच–गाने और लजीज पकवान इस एक्सपीरिएंस को और भी खास बना देते हैं।

यहां तक पहुंचना अब पर्यटकों के लिए काफी आसान है। आप ग्वांगजू शहर से सड़क मार्ग से सीधे यहां आ सकते हैं या फिर मोकपो तक ट्रेन का सफर करके आगे नाव से द्वीप तक पहुंच सकते हैं। यहां पहुंचने पर भीड़ और साइनबोर्ड आपको खुद–ब–खुद उस जगह तक ले जाते हैं।

समुद्र के इस रहस्य के अलावा, जिंदो द्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी मशहूर है। शांत किनारे, हरियाली से ढके पहाड़ और बेहतरीन ट्रेकिंग रूट्स सैलानियों को खूब लुभाते हैं। इसके अलावा, यह जगह अपनी बहादुरी के लिए पहचाने जाने वाले शजिंदो डॉग्सश का भी घर है, जहां इन कुत्तों से जुड़ा एक खास म्यूजियम भी मौजूद है। कुल मिलाकर, यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें बताता है कि हमारी दुनिया कितने अनसुलझे और खूबसूरत रहस्यों से भरी है।

हीट एग्जॉर्शन से हीट स्ट्रोक तक, आयुष मंत्रालय ने बताए गर्मी से बचाव के उपाय

नई दिल्ली, 29 अप्रैल।

देशभर में गर्मी का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ही कई राज्यों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में और भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। गर्मी की इस तपिश से लोगों की सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है। ऐसे में समय रहते सावधानी बरतना बेहद जरूरी है।

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने आम जनता से अपील की है कि वे गर्मी से जुड़ी बीमारियों से बचने के लिए आवश्यक उपाय अपनाएं। मंत्रालय के अनुसार, गर्मी से होने वाली बीमारियों को रोका जा सकता है, अगर सही समय पर सही कदम उठाए जाएं तो इनसे बचाव संभव है।

सबसे पहले तो भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच अपनी सेहत के प्रति लापरवाह न बनें। यदि अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो तुरंत किसी ठंडी जगह पर जाएं और पर्याप्त पानी पीकर खुद को अच्छी तरह हाइड्रेटेड रखें और अपने शरीर के तापमान पर नजर बनाए रखें और जरूरत महसूस होने पर बिना देरी किए चिकित्सक से परामर्श लें।

गर्मी के बढ़ते प्रकोप में सबसे आम समस्या हीट एग्जॉर्शन या गर्मी से थकान और हीट स्ट्रोक है। अगर कोई व्यक्ति अचानक अस्वस्थ महसूस करने लगे, चक्कर आए, मांसपेशियों में ऐंठन हो, ज्यादा पसीना आए या पसीना आना बंद हो जाए, तो इसे गंभीर लक्षण माना जाना चाहिए। ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट तुरंत कुछ जरूरी उपाय की सलाह देते हैं।

इसके लिए व्यक्ति को तुरंत ठंडी और हवादार जगह पर ले जाएं, शरीर का तापमान बार–बार जांचते रहें, इलेक्ट्रोलाइट

युक्त तरल पदार्थ जैसे नींबू पानी, नमक–शक्कर का घोल, छाछ या ओरली रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ओआरएस) का सेवन करें। सादा पानी के साथ–साथ इलेक्ट्रोलाइट्स से शरीर को हाइड्रेट रखें। लक्षण गंभीर होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लें और डॉक्टर से संपर्क करें।

आयुष मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि गर्मी के मौसम में हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनें, दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक धूप में बाहर निकलने से बचें और घर के अंदर भी पर्याप्त वेंटिलेशन रखें। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को गर्मी का सबसे ज्यादा खतरा होता है। इसलिए इनकी खास देखभाल की जरूरत है।–आईएएनएस